

अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस, 11 अक्टूबर

दुनिया से लड़ती, आगे बढ़ती : लड़की

डॉ० घनश्याम बादल

अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस का इतिहास अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बालिका दिवस मनाने की पहल एक गैर-सरकारी संगठन 'प्लान इंटरनेशनल' प्रोजेक्ट के रूप में की गई थी। इस संगठन ने "क्योंकि मैं एक लड़की हूँ" नाम से एक अभियान शुरू किया था। इसके बाद इस अभियान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करने के लिए कनाडा सरकार से संपर्क किया तो कनाडा सरकार ने संयुक्त राष्ट्र की 55 वीं आम सभा में इस प्रस्ताव को रखा और संयुक्त राष्ट्र ने 19 दिसंबर, 2011 को इस प्रस्ताव को पारित कर दिया। इसके लिए 11 अक्टूबर का दिन चुना गया इस प्रकार पहला अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर, 2012 को मनाया गया और उस समय इसकी थीम थी "बाल विवाह को समाप्त करना"।

किसी भी देश को सफल बनाने के लिए बालिकाओं का भी कदम से कदम मिलाकर चलना आवश्यक है जैसे तो लड़के - लड़की को बराबर स्तर और अधिकार देने की मांग बहुत आम है। मगर आज भी बहुत से देश ऐसे हैं जिनमें लड़के लड़की में भेदभाव किया जाता है। कुछ देशों में अपनी - अपनी परिस्थितियों के अनुसार वहां बालिका दिवस जैसे आयोजन किए जाते हैं।

देखें तो आज भी पूरी ही दुनिया बालिकाओं की हालत खराब है। गरीब अफ्रीकी व एशियाई व दक्षिणी एशियाई मुल्कों में तो लिंग भेद से बालिकाओं का हाल बेहाल है। एक सर्वे के मुताबिक

अकेले भारत में 2019 में करीब 8.3 लाख कन्याओं की भ्रूण हत्या हुई यानि उन्हे जन्म लेने से पहले ही मार डाला डाला गया । इनमें भी चिकित्सीय कारणों से ऐसा कदम बहुत कम उठाया गया । पूर्ण प्रतिबंध के बाद भी उन्हे केवल इस लिए मार डाला गया क्येकि वें लड़कियां थी और तकनीकों के जरिए उनके जन्म से पहले ही यह जान लिया गया था । अगर यही हाल रहा लिंगानुपात बिगड़ना तय है और जैसे जैसे लिंग दर में अंतर आएगा अनेक समस्याएं पैदा होंगी । भारत में ही लिंगानुपात असंतुलन के आंकड़ें भय पैदा करने वाले हैं । जनगणना आंकड़ों के मुताबिक 1991 में देश में प्रति एक हजार बालकों पर 972 बालिकाएं थीं । जबकि 2001 की जनगणना में एक हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 933 मात्र रही , । वहीं 2011 में 861 बालिकाएं प्रति एक हजार लड़कों पर दर्ज की गई थी और वर्तमान में यह आठ सौ से भी कम आंकी जा रही हैं । राजधानी दिल्ली समेत भारत के उत्तरी राज्य कहीं ज्यादा भयावह स्थिति में हैं । मगर केरल जैसे राज्य जहां शिक्षा की दर उच्च है वहां बलिकाओं का जन्म प्रतिशत और रोजगार व शिक्षा का प्रतिशत लड़कों से ऊपर है ।

आखिर हम बच्चियां क्यों नहीं चाहते ? या उन्हे गर्भ में ही क्यों मार डालने पर उतारु हैं । आइए, एक नज़र उन परिस्थितियों पर डालें जिन की वजह से हर मां बाप बेटे को बेटियों पर वरीयता देते हैं । गरीबों में बेटा जन्म इसलिए ज्यादा डर पैदा करता है क्योकि उसके शादी ब्याह बेहद महंगे हो गए हैं , पढ़े लिखे रोजगार में लगे वर व अच्छे घर नहीं मिलते हैं , मिलते भी हैं तो दहेज की भारी मांग जान निकालने की हद तक जा रही है । उत्तर व मध्य भारत में खासतौर पर दहेज , छेड़छाड़ की घटनाएं , बलात्कार , शिक्षा व पालन पोषण पर बढ़ता बेतहशा खर्च , बेटे बेटा का भेदभाव व समाज की दकियानूशी सोच मुख्य वजह है । दुखद यह भी है कि समाज दहेजरहित शादियों के लिए आगे नहीं आ रहा है और प्रेम विवाह व सामूहिक विवाह या कोर्ट मैरिज करना अपमान का द्योतक है आद भी समाज में ।

उफ़ ! ये बेदर्द दुनिया :

करने व कहने में दोहरापन है , लड़कियों की शादी के बाद भी सुरक्षा की गारंटी नहीं गयी है , दहेज हत्याएं व प्रताड़नाओं की दर लगातार बढ़ रही है विवाह को दो आत्माओं का मिलन मानने वाले हिन्दू समाज में भी तलाक की दर बहुत उच्च हो गई हैं । सरकार के तमाम प्रयासों के बाद भी मुसलमानों में आज भी तीन तलाक की कुप्रथा रुकने का नाम नहीं ले रही है ।

कानून तो है पर बेअसर व अव्यावहारिक हैं । तलाक की दर 34 प्रतिशत तक जा पहुंची है जो भयावह है । पुनर्विवाह में दिक्कतें होती हैं, दूसरी शादी करने वाली लड़की को आज भी समाज अच्छी नज़र से नहीं देखता , विवश होकर समझौता ही करना ही पड़ता है लड़की को ।

एक लड़की हजार खतरे :

आज लड़की खतरे में है। उसे उस सभ्य समाज से अपने अस्तित्व के लिए लड़ना पड़ रहा है जो उसे कभी पूजता है तो कभी मारता दुत्कारता है । पाखंडी व आडंबरी समाज अपनी जननी को ही जड़ों से उखाड़ फेंकने पर आमादा है। बेटी के नाम पर सौ - सौ कसमें खाने वाले ही उसे पीड़ा दे रहे हैं। बेटी को पराई कहने वालों ने कभी उसे हृदय से स्वीकार किया ही नहीं। दुखद पहलू यह है कि बेटी के शोषण की शुरुआत हमारे घरों से होती हुई समाज में फैल गई है।

आस भी जगी है :

आज कस्बों व शहरों में 'बालिका बचाओ ' व 'महिला सशक्तिकरण' विषयों पर चर्चाएं व सेमिनार तो बहुत होते हैं पर यथार्थ में बेटियां आज भी 'बेचारी' हैं। उनके खान-पान से लेकर शिक्षा व कार्य में उनसे भेदभाव हमारे समाज में आम बात है। दुखद तो पहलू ये है कि इस परंपरा के वाहक अशिक्षित व निम्न व मध्यम वर्ग ही नहीं है बल्कि उच्च व शिक्षित समाज भी है। आज डरी हुई लड़कियों को घर में रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। घर से शुरू होने वाले शोषण की वे बाद में इतनी आदी हो जाती हैं कि अपने ऊपर होने वाले अत्याचार को भी वे हँस कर सहन लेती ।

चिंता जगाते आंकड़े :

लगातार घटती बेटियां की संख्या भारी चिंता का सबब होना चाहिए पर है नहीं । हालांकि केरल जैसे कुछ राज्यों ने इस घृणित प्रवृत्ति को गंभीरता से लिया और इसे रोकने के लिए अनेक प्रभावकारी कदम उठाए हैं । गुजरात में भी "डीकरी बचाओ " अभियान चला है। हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्य में लिंगानुपात में सुधार और कन्या भ्रूण हत्याएं रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने एक अनूठी स्कीम तैयार की है। इसके तहत कोख में पल रहे बच्चे का लिंग जांच करवा उसकी हत्या करने वाले लोगों के बारे में जानकारी देने वाले को 10 हजार रुपए की नकद इनाम देने की घोषणा की गई है। कन्या धन योजना व गांधी बालिका सुरक्षा योजना कं अंतर्गत पहली कन्या

के जन्म के बाद स्थाई परिवार नियोजन अपनाने वाले माता-पिता को 25 हजार रुपए तथा दूसरी कन्या के बाद स्थाई परिवार नियोजन अपनाने माता-पिता को 20 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान किए जा रहे हैं।

चेतना जरूरी

आज 'बालिका बचाओ, बालिका पढ़ाओ जैसे अभियान' को सफल बनाने के लिए सबकी सक्रिय भागीदारी बहुत जरूरी है। कन्या भ्रूण हत्या रोकने हेतु सामाजिक जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ हमें बालिकाओं को बेटे से बढ़कर मानना होगा कुरीतियों व दहेज लेने - देने से बचना होगा उसका विरोध किए बगैर यह संभव नहीं है । कानूनन दंडित करने के साथ ही दहेज मांगने के साथ ही देने वालों को भी बहिष्कृत करना पड़ेगा एक डर समाज व सरकार दोनों और से हो तो शायद बात बन जाए । हम भले ही बालिकाओं को मार रहे हों पर वें हमें गौरवान्वित कर रही हैं । खेलों में सबसे ज्यादा पदक , पढ़ाई में अक्वल , घर के काम में कुशल , ज्ञान विज्ञान में उत्कृष्ट , वायुयान उड़ाएं , सेना में लड़ें , मां बाप का ख्याल रखें , भाई को पालें आखिर क्या नहीं करती बालिकाएं।

कृपया रचनाकार को मेल भेज कर अपने विचारों से अवगत करायें 
